

प्रेषक,

श्रीधर बाबू अददांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग विभाग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 28 दिसम्बर, 2015

विषय: अनुदान संख्या-23 मुख्य लेखा शीर्षक-2853 अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग-02-खानों का विनियमन तथा विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन (लघुशीर्षक 003 के स्थान पर)-03-खनन प्रशासन का अधिष्ठान आयोजनेत्तर पक्ष में अनुपूरक अनुदान मांग के माध्यम से प्रावधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-1861/लेखा/भूखनि०इ०/2014-15 दिनांक 17 नवम्बर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 में खनन प्रशासन का अधिष्ठान आयोजनेत्तर पक्ष की योजनान्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से प्रावधानित धनराशि ₹ 1800 हजार (₹ अठारह लाख मात्र) आपके निर्वर्तन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि हजार ₹ में)

2853-अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग-02- खानों का विनियमन तथा विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन (लघुशीर्षक 003 के स्थान पर)-03-खनन प्रशासन का अधिष्ठान	
मानक मद	धनराशि
04- यात्रा व्यय	100
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	100
06-अन्य भत्ते	400
08-कार्यालय व्यय	20
10-जलकर/जल प्रभार	10
13-टेलीफोन पर व्यय	70
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1100
योग	1800

- (1) धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फॉट कर उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०-8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

- (3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार मासिक रूप से आहरण किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।
- (4) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या संबंधित इकाई में समकक्ष स्तर से स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा शासन की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।
- (5) धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिकों के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें धनराशि व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2853-अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग-00-आयोजनेतर-02-खानों का विनियमन तथा विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन (लघुशीर्षक 003 के स्थान पर)-03-खनन प्रशासन का अधिष्ठान की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-400/XXVII(1)/2015 दिनांक 1 अप्रैल, 2015 एवं शासनादेश संख्या-1336/XXVII(1)/2015 दिनांक 17 नवम्बर, 2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीधर बाबू अददांकी)
अपर सचिव

संख्या- 1799 (1)/VII-1/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
6. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी०एस० भाकुनी)
उप सचिव